

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में:- “दूरस्थ शिक्षा और आईसीटी का विश्लेषणात्मक अध्ययन”

डॉ० जय प्रकाश

सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
रुद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर)

Received: 19/10/2025 | Accepted: 28/11/2025 | Published: 30/12/2025

सारांश

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के तीव्र विकास और कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव के कारण शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी-2020) शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना, शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना और शैक्षिक प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और आईसीटी समावेशी और समान शिक्षण अवसर प्रदान करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईसीटी-संचालित शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह किसी भी समय और कहीं भी सीखने को सुगम बनाती है, जिससे ज्ञान अर्जन अधिक लचीला और गतिशील हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, दूरस्थ शिक्षा ने विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को पारंपरिक कक्षाओं की बाधाओं से मुक्त होकर विश्व स्तरीय शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब और इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री के व्यापक उपयोग से छात्र उद्योग-संबंधी कौशल विकसित कर सकते हैं और रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा पर दिए गए विशेष बल से यह सुनिश्चित होता है कि भारत आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हो। यह शोधपत्र इस बात का विश्लेषण करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार दूरस्थ शिक्षा का सक्रिय रूप से समर्थन करती है, और डिजिटल शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी भूमिका पर बल देती है।

मुख्य बिन्दु: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, खुली और दूरस्थ शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल शिक्षा, लचीली शिक्षा।

प्रस्तावना

आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, ज्ञान और सूचना युवा मस्तिष्क को आकार देने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा अब केवल भौतिक कक्षाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें चर्चा, वाद-विवाद, संवादात्मक गतिविधियाँ और स्व-गति से सीखने जैसी विविध विधियाँ शामिल हैं। प्राचीन भारत में, छात्र गुरुकुल प्रणाली में अपने शिक्षकों के साथ रहते थे और गहन शिक्षण अनुभवों में संलग्न होते थे। समय के साथ, संस्थागत शिक्षा ने इस प्रणाली का स्थान ले लिया और छात्र स्कूलों और कॉलेजों में जाने लगे। हालाँकि, तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ, आधुनिक शिक्षार्थियों के पास अब डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके दूरस्थ रूप से अध्ययन करने का विकल्प है।

पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुँच। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा की शुरुआत की, जिसे बाद में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभ में मुद्रित पत्राचार पर आधारित, दूरस्थ शिक्षा एक मजबूत ऑनलाइन शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुई है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) छात्रों को कब,

कहाँ और कैसे सीखना है, इस संबंध में अद्वितीय लचीलापन प्रदान करती है, जिससे यह कामकाजी पेशेवरों, गृहिणियों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों सहित विविध समूहों के लिए एक आदर्श समाधान बन जाता है।

सभी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा ऑनलाईन एवं पारम्परिक कक्षा शिक्षण के रूप में सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को एक बेहतर आकर्षक शिक्षण अनुभव के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आईसीटी के उपयोग से गुणवत्तापूर्ण वाली ऑनलाईन कक्षाएँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से शिक्षण को रचनात्मक बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आईसीटी का उपयोग महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से शिक्षा के आयामों को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही शिक्षा के प्रति बदलती मांग को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा करने के लिए छात्रों की बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने एवं शिक्षण अधिगम परिणाम को सरल, सुगम, रोचक बनाकर जनसाधारण को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में आईसीटी की अहम भूमिका है। साथ ही दूरस्थ शिक्षा रोजगार प्रदान करने में दृश्य श्रव्य एवं उपग्रह आधारित उपकरणों के माध्यम से सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देती। आज आईसीटी दूरस्थ शिक्षा के लगभग हर पहलू में शामिल है। जैसे प्रिंट, रेडियो, टी0वी0, टेलीग्राम, कम्प्यूटर, सुविधाओं सहित आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म, अध्ययन सामग्री पहुँच और शिक्षक पेशेवर विकास को विस्तृत कर रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य हैं

- डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईसीटी एकीकरण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना।
- लचीले और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना।
- डिजिटल समावेशिता के माध्यम से शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को पाटना।
- व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करना।
- एक समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना जो विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करे।

दूरस्थ शिक्षा और उसका विकास

दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत शैक्षिक अंतराल को कम करने के एक साधन के रूप में हुई थी, जिसे शुरू में दूरस्थ शिक्षा के रूप में जाना जाता था। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ दूर-दूराज में रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था से है, जो किन्ही कारणों से औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु उन्हें शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा एवं लगन है। इस प्रकार उनकी शिक्षा व्यवस्था में अन्तराल हो जाता है। इसीलिए दूरस्थ शिक्षा औपचारिक विकल्प के रूप में दो रूपों में चल रही है। पत्राचार शिक्षा एवं खुली शिक्षा अतः इनके स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। 19 वी शताब्दी में पत्राचार शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित हुआ। जो डाक प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें सीखने से संबंधित अध्ययन सामग्री को सीखने वाले के पास डाक के द्वारा भेजी जाती थी। जिसमें सीखने वाला विद्यार्थी सामग्री का अध्ययन कर अपने दत्त कार्य डाक से वापस भेज देते थे। इसीलिए उस समय इसका स्वरूप अनुदेशन तक ही सीमित था। इसलिए इसे अनुदेशन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार शिक्षा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई। जो कि लोगों का प्राथमिक लक्ष्य होता था। जिसमें लोगों की भौगोलिक स्थिति, वित्तीय बाधाओं और सामाजिक स्थिति से संबंधित बाधाओं को दूर करना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है।

वर्तमान समय में 20 वी शताब्दी में पत्राचार शिक्षा के स्वरूप में कुछ व्यापक परिवर्तन हुए, क्योंकि अब शिक्षा के प्रसार के लिए रेडियो, और टेलीविजन का उपयोग शुरू हो गया था। साथ ही भारत में दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कई शैक्षिक कार्यक्रम और यू0जी0सी0 के देशबन्धु (देशबन्धु कॉलेज) एवं अन्य शिक्षा शृंखला के साथ ही हमारे देश में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से खुले विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में हैदराबाद में हुई। इसका नाम आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय था। जिसे अब वर्तमान में डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत में उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा के लिए कई मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अब पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला उपलब्ध है, जिसमें शैक्षणिक विषयों और कौशल-आधारित व्यावसायिक कार्यक्रमों, दोनों को शामिल किया गया है। कुछ लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में बागवानी, व्यक्तित्व विकास, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बौद्धिक संपदा अधिकार

शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करके उनकी रोजगार क्षमता में भी सुधार करते हैं।

दूरस्थ शिक्षा विशेष रूप से इन लोगों के लिए लाभदायक है

- ग्रामीण और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति
- शिक्षा और कौशल विकास की इच्छुक महिलाएं और गृहिणी
- सड़क पर रहने वाले बच्चे, शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति
- जेल के कैदी जो शिक्षा के माध्यम से समाज में पुनः जुड़ना चाहते हैं
- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है
- पढ़ाई बीच में छोड़ चुके छात्र और कामकाजी पेशेवर जो अपनी शिक्षा फिर से शुरू करना या आगे बढ़ाना चाहते हैं

पारंपरिक कक्षा व्यवस्था के विपरीत, ऑनलाइन शिक्षा में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, पॉडकास्ट, चर्चा मंच और इंटरैक्टिव असाइनमेंट प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र अपनी गति से सीख सकें। दूरस्थ शिक्षा आजीवन सीखने को सक्षम बनाती है, जिससे पेशेवर अपने कौशल को उन्नत कर सकते हैं और अपने कार्य प्रतिबद्धताओं से समझौता किए बिना बदलते करियर की मांगों के अनुकूल हो सकते हैं।

दूरस्थ शिक्षा पर आईसीटी का प्रभाव

आईसीटी के एकीकरण ने दूरस्थ शिक्षा में क्रांति ला दी है, जिससे यह अधिक आकर्षक, संवादात्मक और सुलभ हो गई है। उच्च गति इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता जैसी तकनीकी प्रगति ने छात्रों के सूचना ग्रहण करने और उसे धारण करने के तरीके को बदल दिया है। आज, डिजिटल शिक्षा में अल्पकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से लेकर पूर्ण डॉक्टरेट कार्यक्रम तक, सब कुछ शामिल है।

हालाँकि दूरस्थ शिक्षा तकनीक शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती, लेकिन इसने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। शिक्षक अब केवल ज्ञान प्रदाता से आगे बढ़कर सुविधाप्रदाता और मार्गदर्शक बन गए हैं। पहले, कई छात्र अतिरिक्त शैक्षिक अवसरों से अनजान थे। हालाँकि, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के उदय के साथ, छात्र अब अपनी प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त प्रमाणपत्र और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। सरकार ने ऐसी नीतियाँ भी शुरू की हैं जो छात्रों को एक साथ कई पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की अनुमति देती हैं, जिससे उनके सीखने के अनुभव और करियर की संभावनाओं में वृद्धि होती है— जिसे निम्न बिन्दुओं से समझ सकते हैं।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की आसान पहुँच

आईसीटी ने शिक्षा की गुणवत्ता की पहुँच और परिणामों को पूरी तरह बदल कर शिक्षा को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके द्वारा आजकल विद्यार्थी कहीं पर गांव एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी शिक्षा प्रक्रिया में वीडियो लैक्चर ई-बुक डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अपने अध्ययन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी (विकलांग) जो कहीं भी आने-जाने में असमर्थ हैं वे भी अपनी शिक्षा को आसानी एवं गुणवत्ता पूर्ण के साथ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सुधार

वर्तमान समय में जो विद्यार्थी कहीं भी कार्यरत हैं और अपनी शिक्षा को निरंतर जारी करना चाहते हैं। जो नियमित रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं वे सभी दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करके अपनी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रोचक बनाते हैं। और स्वयं की गति के अनुसार कठिन से कठिन विषय को सरलता एवं स्पष्टता के साथ सीख लेते हैं।

संचार सुधार

आजकल दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने से विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य आमने-सामने (वास्तविका) जैसा शिक्षण में संचार का अनुभव होता है विद्यार्थी अपने शिक्षकों से ऑनलाईन चर्चा-परिचर्चा बेबीनार लाइव कक्षाओं के साथ ई-मेल एवं चैट के माध्यम से शिक्षा में वास्तविकता का प्रभावी संचार से अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हैं।

अध्ययन सामग्री की उपलब्धता

जो भी विद्यार्थी कहीं न कहीं पर कार्यरत है और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। वो दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी का उपयोग कर अपनी सुविधा अनुसार ई-बुक्स ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग लैक्चर (जिन्हें कहीं भी देखा जा सके) अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कर अध्ययन कर सकते हैं।

समय एवं धन की बचत

रोजगार एवं व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं पर उनके पास पर्याप्त समय एवं धन न होने के कारण पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते हैं परन्तु उनकी पढ़ने की इच्छा होती है। वह व्यक्ति दूरस्थ शिक्षा में आईसीटीके उपयोग के माध्यम से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और किफायती एवं सुविधा जनक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिससे उनके धन एवं समय दोनों की बचत होती है।

कौशलों का विकास एवं वैश्विक शिक्षा

विद्यार्थी कौशलों का विकास करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में आईसीटी को शामिल करते जिससे विद्यार्थी में कम्प्यूटर शिक्षा डिजिटल उपकरण ऑनलाईन रिसर्च डेटा प्रबंधन वर्चुअल सहयोग कौशलों को भी सीख सकते हैं। और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात आसानी से रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आईसीटी के उपयोग से विद्यार्थी अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से विदेशी विशेषज्ञ से जुड़कर अपने अंदर शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं।

भारत में शिक्षा नीतियां और नई नीति-2020

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने अपने शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई शिक्षा नीतियां लागू की हैं। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग के अनुशंसा के आधार पर 1968 में लागू की गई थी। 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन वर्ष 1985 में शिक्षा की चुनौतियां – नीति परिप्रेक्ष्य नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इसी के आधार पर 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई, जिसमें सम्पूर्ण देश के लिए एक समान शैक्षिक फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। जिसमें शिक्षा के नियमों में बहुत बड़ा एक बदलाव किया गया था। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा सभी प्रकार के परिवर्तनों (सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बौद्धिक व्यवसायिक) के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा उपकरण है इसी आधार पर कहा गया 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुकी है। पुरानी शिक्षा नीति 1986 अप्रासंगिकता एवं बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावपूर्ण और समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही। कई सामाजिक-राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों ने पिछली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है। शिक्षा के बदलाव के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारिया शुरू कर दी। वर्ष 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया, जिसने 29 जुलाई 2020 में भारत के केन्द्रीय मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। जो भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले ली है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पाठ्यक्रम संवर्धन पर जोर देकर एक प्रतिमान में परिवर्तन लाती है। यह नीति भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने, डेटा-आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने और समग्र शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एकीकरण की वकालत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और खुली दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 डिजिटल शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को स्वीकार करती है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं

1. ऑनलाइन शिक्षा पायलट अध्ययन

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ), इग्नू और आईआईटी जैसे संस्थान ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अनुसंधान करेंगे। ये अध्ययन नवीन समाधान विकसित करने और डिजिटल थकान और स्क्रीन की लत जैसी चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होंगे।

2. डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल अवसंरचना में निवेश पर जोर देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शैक्षणिक संस्थान तकनीकी रूप से सुसज्जित रहें और उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हों।

3. ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों का विस्तार

स्वयं और दीक्षा जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाएगा ताकि शिक्षकों को छात्रों की प्रगति पर नजर रखने और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।

4. डिजिटल शिक्षण सामग्री का विकास

सहभागिता और संवादात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आभासी वास्तविकता (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) संसाधनों सहित एक व्यापक डिजिटल भंडार विकसित किया जाएगा।

5. डिजिटल विभाजन को पाटना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक पहलों के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्राप्त हो। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सामग्री कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

6. वर्चुअल लैब की स्थापना

स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करेंगी, जिससे सभी छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा सुलभ हो सकेगी।

7. शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता

शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों, विषय-वस्तु निर्माण और छात्र सहभागिता तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8. ऑनलाइन मूल्यांकन की शुरुआत

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) छात्रों के अधिगम परिणामों और दक्षताओं का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए नए मूल्यांकन मॉडल लागू करेगा।

9. मिश्रित शिक्षण पद्धतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एक हाइब्रिड मॉडल को प्रोत्साहित करता है जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण को डिजिटल शिक्षा के साथ जोड़ता है, जिससे एक संतुलित और लचीला दृष्टिकोण मिलता है।

10. ऑनलाइन शिक्षा का मानकीकरण

नेटएफ जैसे संगठन डिजिटल शिक्षा की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मानदंड स्थापित करेंगे।

निष्कर्ष

दूरस्थ शिक्षा संस्थाएँ शैक्षिक अनुदेशों के लिए मुद्रित सामग्री पर निर्भर रहती थी वर्तमान में आईसीटी के उपयोग से अमुद्रित सामग्री का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जिससे दूरस्थ शिक्षा संस्थाएँ अपने प्रभावशाली सम्प्रेक्षण में आईसीटी का उपयोग कर औपचारिक संस्थाओं की कमी को पूरा करने में कारगर साबित हो रही है। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा आज के युग डिजिटल युग की एक अनिवार्य और प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली बन चुकी है। जो शिक्षा व्यवस्था को लोकतांत्रिक सुलभ और समावेशी बनाती, तकनीकी विकास और सरकारी पहल के साथ इसका भविष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उज्ज्वल होता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किये जाने वाले परिकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच सही दिशा में कायम है। जो सभी आयामों में गुणवत्ता वाले उपकरण शैक्षिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेगा जो शिक्षा के क्षेत्र के भीतर आईसीटी के माध्यम से सीखने की पहुँच, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, की गुणवत्ता और शिक्षण प्रणालियों के प्रबन्धन के साथ उनकी समस्या का समाधान करने की अपार सम्भावना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक दूरदर्शी नीति है जो डिजिटल रूप से सशक्त शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है। अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को एकीकृत करके, यह शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और कौशल-उन्मुख बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की सफलता सुदृढ़ कार्यान्वयन रणनीतियों, डिजिटल अवसंरचना में पर्याप्त निवेश और शिक्षकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों पर निर्भर करती है। यदि इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है, तो इसमें भारत में शिक्षा में क्रांति लाने, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और छात्रों को 21वीं सदी की बदलती मांगों के लिए तैयार करने की क्षमता है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व 1986 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार।
3. सिंघल, महेश चन्द्र भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं।
4. एंडरसन, जे0 (2010) आईसीटीट्रासफार्मिंग एजुकेशन: ए रीजनल गाइड, यूनस्को।
5. सिंह आर0 (2013) आईसीटीयूज अमांग डिस्टेंस लर्नलस एण्ड दियर एकेडमिक परफार्मेंस ए मल्टीडिसीपलीनरी स्टडी, इंटरनेशनल जनरल ऑफ इनहेस्ट रिसर्च इन एजुकेशनल डवलपमेंट वॉयल्यूम 1 इश्यू 7 नवम्बर, दिसम्बर 2013।
6. रहमान, एच0 (2014) द रोल ऑफ आईसीटीइन ओपन एण्ड डिस्टेंस एजुकेशन टूरकिंस ऑनलाईन जनरल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अक्टूबर 2014 वॉयल्यूम: 15 नम्बर: 4 आर्टिकल।
7. रुचि, आर्या हरीश (2020) दूरस्थ शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकियों की भूमिका ज्ञानेश्वरम , इंटरनेशनल साइंटिफिक रिफर्ड रिसर्च?
8. जनरल 2020 GISRRJ वॉयल्यूम 3 इश्यू 1 ISSN: 2582-0095
9. कुमारी ,मीरा (2020) आधुनिक तकनीकियां एवं शिक्षा का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, जनरल ऑफ इमर्जिंग टैक्नोलॉजी एण्ड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR) ISSN: 2349 -5162 YEAR 2014 MONTHLY ISSUE
10. वर्मा संजय कुमार (2020) में आईसीटी और शैक्षिक नवाचार की भूमिका इंटरनेशनल जनरल ऑफ अप्लाइड रिसर्च ISSN PRINT: 2394-7500, ISSN ONLINE 2394-5869
11. सिंह,विमलेश कुमार (2025) आईसीटीआधारित शिक्षण का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव, इंटरनेशनल जनरल ऑफ नोवल रिसर्च एण्ड डबलपमेंट (IJNRD)। IJNRD, ORG ISSN: 24564184

Cite this Article:

डॉ० जय प्रकाश, (2025) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में:- “दूरस्थ शिक्षा और आईसीटी का विश्लेषणात्मक अध्ययन”.

Chaitanya Samvad Interdisciplinary Journal of Research, 1(3), 26–31.

Doi: <https://doi.org/10.65250/chaitanyasamvad.v1i3.3>

Journal URL: <https://chaitanyasamvad.com/>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

चैतन्यासम्वद इवलयवद

Conscious Conversations | Meaningful Connections